

गणि वर्कर्स: अदृश्य कार्यबल

प्रलिमिस के लिये: [गणि एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, वशिव आरथिक मंच, ई-शर्म पोर्टल।](#)

मेन्स के लिये: भारत की आरथिक वृद्धि में गणि इकोनॉमी की भूमिका, भारत में गणि इकोनॉमी से जुड़े प्रमुख मुद्दे।

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

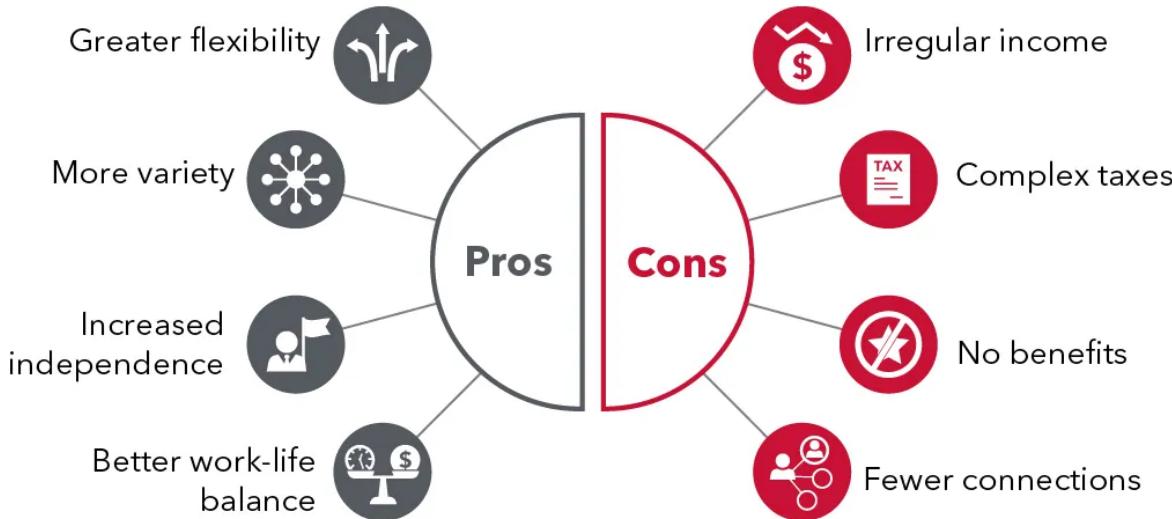
भारत की [गणि और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी](#) तेजी से बढ़ रही है, जिसके 2024-25 में 1 करोड़ कर्मचारियों से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाने का अनुमान है। हालाँकि यह अनुकूलता और नए अवसर प्रदान करती है, लेकिन गणि वर्कर्स काफी हद तक अदृश्य शर्म करते हैं, फिर भी उनके वेतन, नौकरी की असुरक्षा और एलगोरियम-संचालित प्रबंधन के दबाव का सामना करना पड़ता है।

गणि इकोनॉमी क्या है?

- परिचय: [वशिव आरथिक मंच \(WEF\)](#) के अनुसार गणि इकोनॉमी वह व्यवस्था है, जिसमें शर्म का आदान-प्रदान धन के बदले व्यक्तियों या कंपनियों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। ये प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों से अल्पकालिक और प्रति-कार्य भुगतान (payment-by-task) के आधार पर सक्रिय रूप से जोड़ते हैं।
 - सामाजिक सुरक्षा संहति, 2020 के अनुसार गणि वर्कर वह व्यक्ति है, “जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर करनी कार्य का निषिद्धन करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जति करता है।
- गणि वर्कर्स के प्रकार:
 - प्लेटफॉर्म-आधारित कर्मचारी: डिजिटल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे- फूड डलीवरी (जॉमैटो, स्वर्गी), राइडशेयरिंग (ओला, उबर), ई-कॉमरस डलीवरी (अमेज़न, डंजो)।
 - नॉन-प्लेटफॉर्म कर्मचारी: पारंपरिक कषेत्रों में अंशकालिक या पूरणकालिक, अस्थायी या स्व-नियोजित कर्मचारी। उदाहरणों में अंशकालिक ट्यूटर, फ्रीलांस डिजिटाइज़ेशनर, स्व-नियोजित घरेलू सहायक, अस्थायी नरिमाण शर्मकि शामिल हैं।
- गणि इकोनॉमी के लाभ:
 - शर्मकिं के लिये: अनुकूल कार्य समय अवधि, आय के अनेक स्रोत, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर, कौशल विकास।
 - उपभोक्ताओं के लिये: तीव्र सेवाएँ, सुविधा, प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निरिधारण, व्यापक विकल्प।
 - व्यवसायों/प्लेटफॉर्म्स के लिये: वसितार योग्य कार्यबल तक पहुँच, नमिन प्रचालन लागत, बदलती मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता।

GIG ECONOMY PROS AND CONS

Workers in a gig economy can enjoy a number of advantages, but there also are potential disadvantages. The pros and cons include:



गणि इकोनॉमी के विकास चालक क्या हैं?

- डिजिटल पहुँच का वसितार: [डिजिटल इंडिया](#) के तहत, भारत में इंटरनेट कनेक्शन वर्ष 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर 2024 में 96.96 करोड़ हो गए, जिसमें 85.5% घरों में स्मार्टफोन है। डिजिटल पहुँच में इस वृद्धि ने श्रमिकों और नयिकाओं को जोड़कर गणि इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा दिया है।
- ई-कॉमर्स और स्टार्टअप बूम: ऑनलाइन व्यवसायों और स्टार्टअप्स के बढ़ने से लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, मार्केटिंग और कंटेंट निर्माण में गणि वर्कर्स की मांग बढ़ रही है।
- सुविधा के लिये शहरी मांग: उपभोक्ता तेजी से सेवाओं की अपेक्षा कर रहे हैं, जिससे खाद्य वितरण, राइडशेयरिंग और ग्राहक सहायता के अवसर बढ़ रहे हैं।
- कम लागत वाले श्रम की उपलब्धता: बढ़ती [रोजगारी](#) और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की अधिकता के कारण कई लोग आय के स्रोत के रूप में गणि कार्य को स्वीकार करने लगे हैं।
- बदलती कार्य प्राथमिकताएँ: युवा पीढ़ी अनुकूलता, दूरस्थ कार्य और परियोजना-आधारित कार्यों को महत्व देती है, जिससे गणि भूमिकाएँ अधिक आकर्षक हो जाती हैं।

गणि इकोनॉमी के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- कम वेतन और आय अस्थिरता: गणि वर्कर्स को कम, अप्रत्याशित वेतन का सामना करना पड़ता है, उन्हें नशिचति वेतन के बजाय प्रतिकार्य कमाई होती है, अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दबाव का सामना करना पड़ता है जो "अनुकूलता" और पूरणकालिक रोजगार के बीच की रेखा को कर देता है।
- सीमित कानूनी और सामाजिक सुरक्षा: न्यूनतम कानूनी सहायता और श्रम कानूनों में अपर्याप्त मान्यता के कारण गणि वर्कर्स असुरक्षित हो जाते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा संहति, 2020 गणि वर्कर्स को स्वीकार करती है, लेकिन न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी और वनियमिति कार्य घंटे जैसे पूरण श्रम अधिकार प्रदान करने में वफिल रहती है।
- गरमी, बीमारी या दुरघटनाओं जैसे संकटों के दौरान, जब कोई औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, कमजोरियाँ बढ़ जाती हैं।
 - गणि वर्कर्स को कर्मचारी नहीं बल्कि "स्वतंत्र टेकेवार" माना जाता है, जिससे उन्हें नयिमति घंटों और सवेतन अवकाश से वंचति रहना पड़ता है, जबकि वे अक्सर पूरणकालिक कार्य करते हैं।
- एलगोरिद्म नियंत्रण और निगरानी: डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रमिकों के स्थान को ट्रैक करते हैं, प्रदर्शन की निगरानी करते हैं तथा कभी-कभी

सेवा के दौरान उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक उत्पाद की स्कैनिंग की भी आवश्यकता होती है।

- एलगोरेडिम कठोर कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, देरी पर दंड लगाते हैं तथा बनि कर्सी मानवीय निगरानी के करमचारियों के बलॉक कर सकते हैं। इससे लगातार दबाव बनता है, जिससे करमचारियों पर अनुपालन करने का दबाव बनता है, अन्यथा उनकी आय कम होने का जोखिम रहता है।

- सामाजिक सुरक्षा और लाभों का अभाव:** गणि शरमकिं को आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर, मातृत्व लाभ, भविष्य निधि और पेंशन जैसे लाभों से वंचित रखा जाता है।

- ग्रमी की लहरों, बीमारी या दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं के समय, उनके पास कोई औपचारिक सुरक्षा तंत्र न होने के कारण उनकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है।

- लगि-विशिष्ट कमज़ोरियाँ:** महलियों को, विशेष रूप से सफाई या सौंदर्य सेवाओं जैसी भूमिकाओं में, ग्राहकों से उत्पीड़न और घर पर घरेलू हस्तियों का सामना करना पड़ता है।

- कार्य के लिये नजी घरों में प्रवेश करने से असुरक्षित परस्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म की रेटिंग और दंड प्रणाली अक्सर महलियों को असुरक्षित बना देती है तथा उनके पास कानूनी सहारा बहुत कम होता है।

- शारीरिक दबाव:** गणि कार्य का कोई निश्चयित समय नहीं होता; "अनुकूलता" (flexibility) का अरथ अक्सर 24 घंटे कार्य पर उपलब्ध रहना होता है।

- इससे लंबे कार्य घंटे, सख्त समय-सीमाएँ (deadlines) और नरिंतर लक्ष्य-आधारित दबाव उत्पन्न होता है, जो शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बनता है।

भारत गणि इकोनॉमी की चुनौतियों का समाधान कैसे कर रहा है?

- सामाजिक सुरक्षा संहति, 2020:** इसमें गणि और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता दी गई है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये गए हैं। इस संहति में गणि और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का प्रावधान भी है।

- नीतिआयोग का RAISE फ्रेमवर्क गणि और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिति करता है।** यह पाँच मुख्य बहुओं पर केंद्रित है:

- R – **Recognise:** कार्य विधिता को मान्यता देना

- A – **Augment:** वित्तीय सहयोग बढ़ाना

- I – **Incorporate:** प्लेटफॉर्म और वर्कर्स के हतियों को शामिल करना

- S – **Support:** जागरूकता को समर्थन देना

- E – **Ensure:** लाभ तक पहुँच सुनिश्चिति करना

- ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal):** वर्ष 2021 में शुरू किया गया यह पोर्टल असंगठित और गणि वर्कर्स का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करता है। इसके माध्यम से शरमकिं को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जाता है तथा उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है। इस पोर्टल का उद्देश्य कार्यबल का औपचारिकरण (formalisation) करना और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में सुधार लाना है।

- अगस्त 2025 तक 3.37 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म और गणि वर्कर्स इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

- राज्य-स्तरीय उपाय:** राजस्थान के प्लेटफॉर्म-आधारित गणि शरमकि अधिनियम (2023) के तहत नियोक्ताओं को कल्याण उपकर जमा करना आवश्यक है।

- कर्नाटक ने गणि वर्कर्स वेलफेर बोर्ड (2024) का प्रस्ताव रखा है तथा तेलंगाना ने गणि वर्कर्स के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये एक विधियक का मसौदा तैयार किया है।

कौन से उपाय भारत की गणि अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर सकते हैं?

- व्यापक कानूनी ढाँचा:** गणि वर्कर्स के अधिकारों और जमिमेदारियों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करना। न्यूनतम वेतन, विनियमिति कार्य घंटे, अनुचित बर्खासंतर्ग से सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के प्रावधान शामिल किये जाएं।

- महलियों केंद्रित उपाय:** सुनिश्चिति करना की महलियों सामाजिक सुरक्षा संहति, 2020 के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकें। देखभाल और घरेलू जमिमेदारियों को समायोजित करने के लिये दूरस्थ और परियोजना-आधारित भूमिकाओं को बढ़ावा देना।

- ऐप्स पर पैनकि बटन, ग्राहकों और डिलीवरी पॉइंट्स का बैंकग्राउंड सत्यापन तथा महलियों गणि वर्कर्स के लिये समर्पण हेल्पलाइन शुरू करना।

- एलगोरेडिम संबंधी निषिपक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चिति करना:** मनमाने ढंग से आय की हानियों को रोकने के लिये कार्य आवंटन, रेटिंग और दंड निर्धारित करने वाले प्लेटफॉर्म एलगोरेडिम को विनियमिति करना।

- सवालालिति नियमों से प्रभावित शरमकिं के लिये शक्तियां निवारण, मानवीय नरीकृष्ण और अपील तंत्र को अनिवार्य बनाना।

- डिजिटल साक्षरता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना:** गणि अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सक्षम करने के लिये ग्रामीण और अरद्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच का विस्तार करना।

- अस्पष्ट कॉरपोरेट नीतियों पर नियमिति करना:** गणि अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सक्षम करने के लिये शरमकिं को अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सुरक्षित मंच प्रथाओं के बारे में शक्षिति करना।

- प्लेटफॉर्म अनुपालन को प्रोत्साहित करना:** कर छूट, सबसिडी या अधिमान्य सरकारी अनुबंध जैसे प्रोत्साहनों को कल्याणकारी कानूनों और

- नाषिपक्ष भुगतान प्रथाओं के पालन से जोड़ना।
 - प्लेटफार्मों को स्वेच्छा से अनुपालन करने और एक स्थायी गणि पारस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करना।
- ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से औपचारिकता: गणि श्रमकों को डिजिटल पहचान और कल्याणकारी योजनाओं, रोज़गार बीमा और स्वास्थ्य कवरेज तक पहुँच प्रदान करने के लिये ई-श्रम पोर्टल एकीकरण का वस्तिर करना।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में समावेशन सुनिश्चित करने के लिये गणि श्रमकों पर औपचारिक रूप से नज़र रखना।

नष्टिकरण

भारत की गणि और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था सामाजिक सुरक्षा संहति (2020) और ई-श्रम पोर्टल जैसी पहलों के साथ श्रम बाज़ार को तेज़ी से नया रूप दे रही है। गणि कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और उचित अवसर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये निरंतर समर्थन तथा प्रभावी नीतियाँ अत्यंत महत्वपूरण हैं।

प्रश्न:

प्रश्न. भारत की गणि और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के विकास तथा श्रमकों, उपभोक्ताओं व व्यवसायों पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न:

प्रश्न. भारत में नियोजित अनियित मज़दूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-(2021)

- सभी अनियित मज़दूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं।
- सभी अनियित मज़दूर नियमित कार्य-समय एवं समयोपरी भुगतान के हकदार हैं।
- सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनियोगित कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गणि इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021)